कैसे दूर होगी गांवों में डॉक्टरों की कमी

भारत डोगरा

एक उत्साहजनक समाचार है कि इस वर्ष खुल रहे 6 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में डॉक्टरी पढ़ाई की वार्षिक फीस मात्र बीस हज़ार रुपए रखी गई है जिसमें होस्टल व भोजन खर्च शामिल हैं। ये संस्थान रायपुर, पटना, भोपाल, ऋषिकेश, जोधपुर व भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे।

इस तरह डॉक्टरी शिक्षा को कम आय वर्ग के परिवारों के छात्रों तक पंहुचाने के लिए सरकार को अनेक अन्य चिकित्सा शिक्षा संस्थान व उनसे जुड़े अस्पताल आरंभ करने चाहिए ताकि देश में कम आय वर्ग के परिवारों में छुपी प्रतिभाओं को महंगे प्रायवेट संस्थानों के पर्याप्त विकल्प मिल सकें। इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ने की एक राह यह भी हो सकती है कि चिकित्सा शिक्षा के कुछ नए कम अवधि के कोर्स आरंभ किए जाएं जिनकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहे।

इसकी एक वजह यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में डॉक्टरों की बहुत कमी है। महानगरों में आपको अनगिनत महंगे प्रायवेट नर्सिंग होम मिल जाएंगे, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में तो सरकार का चिकित्सा तंत्र ही सबसे अधिक फैला है और इसमें डॉक्टरों की गंभीर कमी है। योजना आयोग के हाल के एक दस्तावेज़ में बताया गया है कि यहां सामान्य डॉक्टरों की कमी 76 प्रतिशत तक है जबकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी 88 प्रतिशत तक है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। आखिर पूरे देश में चिकित्सा तंत्र फैलाने, उसके भवन बनाने और विभिन्न उपकरण खरीदने का लाभ ही क्या है यदि वहां डॉक्टर ही न हों।

इस चिंताजनक स्थिति से निपटने का एक तरीका यह है कि सरकार कम फीस पर ज़रूरतमंद छात्रों को अच्छी गुणवत्ता की चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध करवाए। ज़रूरत पड़ने पर कम फीस में भी छूट दी जा सकती है व छात्रवृत्तियां भी दी जा सकती हैं। पर साथ में यह अनुबंध जुड़ा रहना चाहिए कि 15-20 वर्ष या एक निश्चित अवधि तक ये छात्र अपनी सेवाएं सरकारी चिकित्सा तंत्र को उपलब्ध करवाएंगे।

इसके लिए उन्हें उचित वेतन के साथ अन्य ज़रूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएं। जैसे गांवों व कस्बों में रहने के लिए व बच्चों की शिक्षा के लिए भी उन्हें सुविधाएं दी जाएं। इस तरह कुछ वर्षों में ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि पूरे देश में फैले सरकारी चिकित्सा तंत्र में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर चुके डॉक्टरों की कोई कमी नहीं रहेगी।

यह प्रयास केवल डॉक्टरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए अपितु सरकारी चिकित्सा तंत्र की अन्य ज़रूरी नियुक्तियों के लिए भी इसी मॉडल को अपनाना चाहिए; पहले सस्ती व अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, और शिक्षा पूरी होने पर इन छात्रों को अच्छे अवसर देकर उनकी सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी चिकित्सा सेवा तंत्र में ली जाएं।

योजना आयोग के हाल के दस्तावेज़ के अनुसार जहां सरकारी चिकित्सा तंत्र में डॉक्टरों की बहुत कमी है, वहीं नर्सों की भी 53 प्रतिशत कमी है, और प्रयोगशालाओं में तकनीकी कर्मियों की 85 प्रतिशत तक कमी है। अतः इन सभी क्षेत्रों में सस्ती व अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवा कर पूरे देश के स्वास्थ्य व चिकित्सा तंत्र को मज़बूत करने का आधार तैयार किया जाना चाहिए। ***(स्रोत फीचर्स)***